

प्रेषक,

संख्या-2764/25-8-95-39/11/70

श्री मोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

॥1॥ उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव
एवं विशेष सचिव ।

॥2॥ समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

गोपन अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 95

विषय:- आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जाँच में दोषी पाये गये अधि-
कारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दिये जाने के
विषय में समय-सीमा का निर्धारण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिकांशतः यह देखा गया है
कि आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जाँचों में आपराधिक कृत्यों के लिए
प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध शासन के सम्बन्धित
विभागों अर्थात् प्रशासकीय विभागों से अभियोजन की शासकीय स्वीकृति काफी
विलम्ब से मिलती है।

2- अतः शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जबकि ई0ओ0डब्लू0
की अन्तिम आख्या शासन के सम्बन्धित विभागों को प्राप्त हो जाय, उस तिथि
के बाद से अधिकतम छः माह के अन्दर आपराधिक कृत्यों हेतु दोषी अधिकारियों/
कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की शासकीय स्वीकृति शासन व उसके सम्बन्धित
विभागों द्वारा अवश्य निर्गत कर दी जाय। सभी प्रशासकीय विभागों तथा
आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से यह भी अपेक्षा की जाती है कि इस हेतु वे
परस्पर तालमेल व सक्रियता पर बल दें ।

उपर्युक्त समय-सीमा का कड़ाई से परिपालन किया जाना अत्यावश्यक
एवं अपरिहार्य है।

भवदीय,

मोहिन्दर सिंह

प्रमुख सचिव,

गृह एवं गोपन ।

.....2/

संख्या - 2764/1/25-8-95-तद्विदनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित :-

- १११ समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- ११२ समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।
- ११३ समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- ११४ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- ११५ समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
- ११६ शासन के समस्त निगमों के अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक।
- ११७ राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- ११८ पुलिस अपर महानिदेशक, अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसन्धान संगठन, उ०प्र०, पंचम तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
- ११९ पुलिस उप महानिरीक्षक, ई०ओ०डब्लू०, उ०प्र०, लखनऊ ।

आज्ञा से,
Amulya
15/11/2195

कृष्ण गोपाल
उप सचिव।